Eastern Council and the hill areas devlopment programme of Assam, is enclosed. (*See* below)

(b) The Central assistance forms a part of the State Plan allocation and is not given project-wise. The details of Central assistance for each State of the north-east for the Annual Plan 1990-91 is given in column 3 of the enclosed statement.

Statement

Approved Annual Plan outlays and Central Assistance (Net) for NEC and North Eastern States and HADF of Assam—1990-91.

(Rs. crores)

	Approve outlays	Central assistance (Net)
North Eastern Council	202	197·00
Assam	675	632·62
Arunachal Pradesh	183	152·56
Manipur	170	145·35
Mizoram.	125	90·58
Meghalaya	175	140·16
Nagaland	145	112 87
Tripura	200	155·79
Sikkim	76	65·37
Hill Area Development Programme of Assam	38·87	38·87

Effect of gases emitted by Mathura Refinery on Taj Mahal

53. SHRI KAMAL MORARKA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the historical Taj Mahal's beauty is being affected by the constant emission of gases from the Mathura Refinery; and

(b) if so, what steps are being taken to protect the monument?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI CHIMANBHAI MEHTA): (a and (b) No, Sir.

The Experts Commissioned by the IOC to study the effects of gaseous emissions from Mathura Refinery on Taj have opined that the level of pollution from the emission from the said refinery is well below the prescribed level and does not pose any threat to the Taj Mahal.

The Archaeological Survey of India is, constantly monitoring the ambient air around Taj for assessing the level of pollutants like sulphur dioxide, etc. in order to take remedial measures as may be required, if any.

स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया के पश्चिम विभागीय क्रीड़ा काम्पलेक्स द्वारा काम बन्द कर दिया जाना

54. डा० बापू कालदाते : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औरंगाबाद (महाराष्ट्र) के क्रीड़ा संगठनों और दैनिक

"मराठवाड़ा" के सम्पादक ने अप्रैल, 1990 में केन्द्रीय सरकार को भेजे गये अपने पत्रों में शिकायत की है कि स्पोर्टस अथॉरिटी ऑफ़ इण्डिया का पश्चिम विभागीय क्रीड़ा काम्प्लेक्स केन्द्र, जिसके लिये 1987 में मंजूरी दी गई थी और जिसके लिये हाल ही में एक निदेशक नाम-निर्देशित किया गया है और जिसके लिये मराठवाड़ा विद्यापीठ ने 100 एकड़ जमीन दी है, धनराशि के अभाव में बिल्कुल काम नहीं कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार उस केन्द्र द्वारा तेजी से कार्य करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) औरंगाबाद, महाराष्ट्र में भारतीय खेल प्राधिकरण के पश्चिम क्षेत्र उपकेन्द्र में विकास के बारे में "मराठवाड़ा" दैनिक के सम्पादक को 21 मई, 1990 का पत्र तथा कुछ जिला खेल एसोसिएशनों और अन्य से भी ऐसी ही सूचना प्राप्त हुई है ।

मैदान की दीवार और आंतरिक सड़कों पर पहले ही 2740 लाख रुपये खर्च किए जा चुके हैं । इसमें महाराष्ट्र सरकार द्वारा 15 लाख रुपये का योगदान शामिल है ।

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में इस केन्द्र के विकास के लिए 2.00 करोड़ रुपये के अपने वादे में से 15.00 लाख रुपये की दूसरी किस्त दी है । केन्द्र के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया गया है तथा सुविधाओं के विकास के लिए आगामी कदम उठाये जा रहे हैं । मई-जून, 1990 के दौरान प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पहले ही संचालित किया गया है ।

(ख) भारत सरकार ने महाराष्ट्र सरकार से उनका सम्पूर्ण वचनबद्ध योगदान देने के लिए मामला उठाया है । इससे इस केन्द्र का विकास कार्य शीघ्र पूरा होगा जिसकी अनुमानित लागत लगभग 5.00 करोड़ रुपये होगी ।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खर्च में कटौती

55. **डा. रत्नाकर पाण्डेय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खर्च में कटौती करने के सरकार के अभियान के अन्तर्गत, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के खर्च में कई मदों के अन्तर्गत कटौती की गयी है ;

(ख) क्या यह सच है कि शिक्षा विभाग के लिए आशयित बजट में भी कटौती की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो यह कटौती किन-किन मदों के अंतर्गत की गयी है और उनका ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशि में इस कटौती के कारण शिक्षा के क्षेत्र में क्या-क्या दिक्कतें आने की सम्भावना है, उनसे कैसे निपटा जायेगा ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिमन भाई मेहता) : (क) से (घ) जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तीनों विभागों अर्थात्—शिक्षा, संस्कृति, और युवा कार्य तथा खेल विभागों के कुल बजट में कोई कटौती नहीं की गयी है, तथापि विदेशी यात्रा पर खर्च को, पिछले वर्ष इस शीर्षक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक खर्चे के 75% तक सीमित करने का निर्णय किया गया है ।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की को कोर्ट बैठकें

56. **डा० रत्नाकर पाण्डय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :